हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

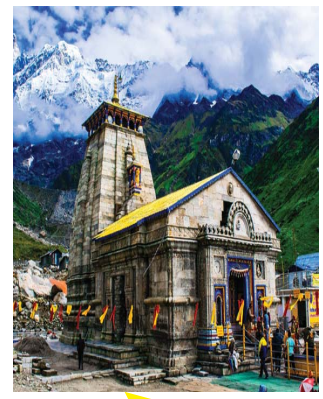

वर्ष:5 अंक:28 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये | pathpravah.com | हरिद्वार, सोमवार, 02 फरवरी 2026

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट...

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, कैंसर की 17 दवाइयां कस्टम ड्यूटी फ्री, 3 आयुर्वेदिक एम्स ; 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट 2026 पेश कर दिया है। यह बजट आम आदमी, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस बताया जा रहा है। इस बजट का कुल साइज 53.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। इस बजट में आम आदमी के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। 7 नए रेल कोरिडोर का ऐलान किया गया है। वहीं गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता कर दिया गया है। लेकिन इस बजट में अभी कई बड़े ऐलान नहीं किए गए हैं, जिसपर आम आदमी को उम्मीद थी कि ये बड़े ऐलान हो सकते हैं और उन्हें बड़ी राहत दी जा सकती है। पिछले बजट में नए इकनम टैक्स रिजीम के तहत आम टैक्सपेयर्स को 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर 0 टैक्स का ऐलान किया गया था, जिसकी लिमिट बढ़ाकर इस बार14 लाख रुपये तक किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। नए टैक्स सिस्टम के तहत पीपीएफ, एनपीएस और ईएलएसएस जैसी योजनाओं में निवेश पर टैक्स छूट दिए जाने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। यह सिर्फ पुराने टैक्स रिजीम के तहत ही छूट के योग्य होंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में इन योजना में निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट दी जाती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 85 मिनट बोलीं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही गई हैं। वित्त मंत्री के भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं था। वे लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंचीं जरूर, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं कीं। वित्त मंत्री ने भाषण में जियो-पॉलिटिक्स

और चुनौतियों का जिक्र किया और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया। इसमें से 2.19 लाख करोड़ सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे। यह रकम पिछले साल 1.80 लाख करोड़ थी।

-बजट की 7 सबसे बड़ी घोषणाएं

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।

कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। अभी 5 प्रतिशत शुल्क लगता था। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयांभी ड्यूटी फ्री।

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई -पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी।

5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान।

15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी।

करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।

किसके लिए क्या

युवाओं के लिए

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मुंबई की मदद से 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगे। एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर के लिए 2030 तक 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा। 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जहां पढ़ाई के साथ कंपनियों में काम का मौका देकर युवाओं को कॉर्पोरेट मित्र बनाया जाएगा। सुदूर इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल नेटवर्क मजबूत करने के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। गेमिंग स्टार्टअप्स को लोन देने के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा। आईआईटी और आईआईएससी में 10,000 नई टेक फेलोशिप शुरू की जाएंगी, जिसमें एआई और डीप-टेक में रिसर्च पर फोकस होगा। एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा जो स्टूडेंट्स को सीधे सर्विस इंडस्ट्री में काम के लिए तैयार करेगा। 20 बड़े टूरिस्ट साइट्स पर 12 हफ्तों का हाइब्रिड ट्रेनिंग कोर्स चलेगा। इससे 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को अप-स्किल किया जाएगा। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित होगा। इससे लोकल रिसर्चर, इतिहासकार और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जॉब के मौके बनेंगे। देश में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना की जाएगी।

महिलाओं के लिए

बिजनेसवुमन को प्रमोट करने के लिए सी-मार्ट स्थापित किए जाएंगे। इसमें क्षेत्रीय कम्युनिटी की महिला दुकानदारों की रीटेल दुकानें होंगी। देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इससे दूर-दराज इलाकों की छात्राएं लैब और रिसर्च के लिए ज्यादा समय दे सकेंगी जिससे हायर एजुकेशन में भागीदारी बढ़ सके। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में महिलाओं को प्रमोट करने के लिए स्पेशल फंड बनाया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे और सीसीटीवी नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष आयुर्वेदिक देखभाल केंद्र खोले जाएंगे।

नौकरी पेशा लोगों के लिए

इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। 2025 में 12 लाख तक की आय टैक्स-फ्री की गई थी। नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 बरकरार है। कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अनिवार्य वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है। 'एजुकेशन टू एम्पलॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेज' कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी एआई समेत उभरती तकनीकों के रोजगार पर पडने वाले असर का आकलन कर सिफारिशें देगी। छोटे उद्यमियों की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा।

किसानों के लिए

खेती को आधुनिक बनाने के लिए मल्टीलैंग्वेज एआई टूल भारत विस्तार लॉन्च किया जाएगा। ये टूल किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती के तरीकों, मौसम की जानकारी और फसल के स्टॉक का अपडेट देगा। अगले एक साल में 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन की जानकारी डिजिटल रजिस्ट्री में शामिल की जाएगी। नारियल उत्पादन बढ़ाने, चंदन की वैज्ञानिक खेती और पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, काजू और कोको की खेती के लिए स्पेशल इंसेटिव दिया जाएगा। अगले दो सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके लिए देशभर में 10,000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फसलों की बर्बादी रोकने के लिए देशभर में फसल भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। मछली पालन के लिए बजट बढ़ाकर 2,352 करोड़ रुपए कर दिया गया है। डेयरी और पशुपालन में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपए सालाना बरकरार रखा गया है। इससे 11.8 करोड़ किसानों को लाभ मिलता रहेगा।

सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट 2026-27 को बताया 'अमृत काल का संकल्प-पत्र'

पथ प्रवाह, नई दिल्ली

पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 केवल संख्याओं का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि अमृत काल का संकल्प-पत्र है, जो समृद्धि की धारा बहाते हुए विकसित भारत के स्वप्न को ठोस आधार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था को सामर्थ्य, अंत्योदय को अभ्युदय तथा साधनों को समाधान में रूपांतरित करने की एक दूरदर्शी यात्रा है। आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप यह बजट घरेलू उद्योगों को गति देने, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और आयात-निर्भरता कम करने की स्पष्ट दिशा तय करता है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आमजन की क्रय-शक्ति को मजबूती तथा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं की व्यापक पहुँच–ये सभी इस बजट की आत्मा हैं। इन्हीं निर्णायक प्रयासों का परिणाम है कि भारत ने

लगभग 7 प्रतिशत की सशक्त विकास दर के साथ गरीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट 'सबका साथ-सबका विकास' के मंत्र के साथ भारत को तेज़ी से आगे बढ़ते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करेगा। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गरीब कल्याण, किसान सशक्तिकरण, मातृशक्ति के सम्मान और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को समर्पित इस लोकहितैषी, दूरदर्शी और राष्ट्रनिर्माणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त किया है।

विकसित भारत-2047 की दिशा में सर्वस्पर्शी बजट : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत ञ2047 के संकल्प को साकार करने वाला सर्वस्पर्शी और दूरदर्शी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शक नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, समृद्ध और वैश्विक नेतृत्व करने वाले भारत का स्पष्ट रोडमैप है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यह बजट आज की जरूरतों के साथ-साथ आने वाले दशकों की चुनौतियों और संभावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। किसान, युवा, नारी शक्ति और वंचित वर्ग इस बजट के केंद्र में हैं। अवसरों के विस्तार, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता को मजबूती और

समावेशी विकास की ठोस योजनाएं इस बजट को विशेष बनाती हैं। उन्होंने बताया कि रक्षा, कृषि, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रावधान देश की आर्थिक गति को नई रफ्तार देंगे। इसके साथ ही सामाजिक संतुलन को मजबूत करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का संकल्प भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विशेष रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में ट्रेकिंग ट्रेल्स के विकास की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह पहल पर्वतीय राज्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे स्थानीय आजीविका को मजबूती मिलेगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पर्यटन के क्षेत्र में नए द्वार खुलेंगे। साथ ही, यह कदम पर्यावरण के अनुकूल विकास और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 निःसंदेह विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की ओर एक निर्णायक कदम है। यह बजट देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है।

बजट 2026-27: लोक-कल्याण और आधुनिकता का संतुलित महासेतु

प्रो. (डॉ.) सुनील कुमार बत्रा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। शिक्षाविद् एवं प्राचार्य, एसएमजेएन कॉलेज डॉ सुनील कुमार बत्रा ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 मात्र आय-व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह बदलते भारत की आकांक्षाओं और वैश्विक चुनौतियों के बीच एक सशक्त 'आर्थिक कवच' के रूप में उभरता है। इस बजट की परतें खोलने पर भविष्य के भारत की तीन स्पष्ट दिशाएँ दृष्टिगोचर होती हैं– शैक्षिक नवाचार, सामाजिक सुरक्षा और सुदृढ़ बुनियादी ढांचा।

शिक्षा सुधार: साक्षरता से आगे नवाचार की ओर

डॉ सुनील बत्रा ने कहा कि बजट में 50 हजार नई अटल टिंकरिंग लैब्स की घोषणा इस बात का संकेत है कि सरकार अब डिग्री-केंद्रित शिक्षा से आगे बढ़कर कौशल, अनुसंधान और नवाचार-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। साथ ही 10 हजार नई मेडिकल सीटों का सृजन स्वास्थ्य शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल ब्रेन ड्रेन पर अंकुश लगेगा, बल्कि मध्यम वर्गीय युवाओं के लिए डॉक्टर बनने का सपना अधिक सुलभ होगा।

मध्यम वर्ग और सामाजिक न्याय का सशक्त संतुलन

डॉ सुनील बत्रा ने कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग को वह राहत प्रदान करता है, जिसकी लंबे समय से अपेक्षा थी। नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय को प्रभावी रूप से कर-मुक्त करना उपभोग को प्रोत्साहित करेगा और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर-छूट की सीमा को दोगुना करना तथा गंभीर बीमारियों में प्रयुक्त 36 दवाओं को सीमा शुल्क से मुक्त करना सरकार की कल्याणकारी राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कुंभ प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर्संबंध

डॉ सुनील कुमार बत्रा ने कहा कि भारत जैसे देश में, जहाँ कुंभ जैसे विशाल मानव समागम आयोजित होते हैं, वहाँ लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बजट में प्रस्तावित 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर तथा 20 राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास ऐसे आयोजनों के प्रबंधन को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएगा। यह बुनियादी ढांचा पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ेगा।

एमएसएमई को संजीवनी

डॉ सुनील बत्रा ने कहा कि 10 हजार करोड़ रुपये का एमएसएमई ग्रोथ फंड छोटे और मझोले उद्यमों के लिए सुरक्षा कवच सिद्ध होगा। यह रोजगार सृजन की उस रीढ़ को मजबूती देगा, जो कोविड-काल के झटकों के बाद पुनः खड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास की गति को बरकरार रखना एक जटिल चुनौती थी, जिसमें वित्त मंत्री काफी हद तक सफल दिखाई देती हैं। हालांकि इस बजट की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि डिजिटल एग्री-स्टैक और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का लाभ ग्रामीण भारत तक कितनी शीघ्रता से पहुँचता है। कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026-27 ज्ञान, विज्ञान और जन-कल्याण का एक संतुलित एवं दूरदर्शी दस्तावेज है, जो भारत को 2047 के विकसित राष्ट्र के संकल्प की ओर मजबूती से अग्रसर करने की क्षमता रखता है।

एक नजर

बजट के एक ऐलान से शेयर बाजार में भूचाल, निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपये स्वाहा

पथ प्रवाह, नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक अहम ऐलान ने शेयर बाजार में भारी उथल-पुथल मचा दी। रविवार को बजट के लिए आयोजित विशेष ट्रेडिंग सत्र में दोपहर के कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों में घबराहट का माहौल बन गया। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 2,370.36 अंक यानी 2.88 प्रतिशत टूटकर 80,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसलते हुए 79,899.42 अंक पर आ गया। वहीं एनएसई निफ्टी 748.90 अंक या 2.95 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 24,571.75 अंक पर बंद हुआ। बाजार में अचानक आई इस गिरावट ने कुछ ही घंटों में निवेशकों की संपत्ति पर बड़ा असर डाला। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देखें तो इस तेज गिरावट के चलते निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ रुपये बाजार से साफ हो गए। बैंकिंग, आईटी, ऑटो और एफएमसीजी समेत लगभग सभी प्रमुख सेक्टरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। खासतौर पर बड़े शेयरों में जोरदार मुनाफावसूली हुई, जिससे सूचकांक और अधिक दबाव में आ गए। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में किए गए कुछ प्रावधानों को लेकर निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ी, जिसका सीधा असर बाजार पर पड़ा। टैक्स और नीतिगत बदलावों की आशंका के चलते निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाते हुए बड़े पैमाने पर बिकवाली की। इसके साथ ही वैश्विक संकेतों की कमजोरी ने भी घरेलू बाजार की धारणा को प्रभावित किया। विशेष ट्रेडिंग सत्र में आई इस गिरावट ने यह साफ कर दिया कि बजट से जुड़ी नीतिगत घोषणाएं बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं। आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर अब सरकार की ओर से मिलने वाली स्पष्टता और बाजार की स्थिरता पर टिकी रहेगी।

बजट 2026 : आम आदमी को राहत, शौक और विलासिता पर बढ़ी मार

पथ प्रवाह, नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने जहां स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कई उत्पादों को सस्ता कर आम लोगों को राहत दी है, वहीं तंबाकू, शराब और लग्जरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर उन्हें महंगा कर दिया गया है। बजट के प्रावधानों का सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ना तय है। बजट के मुताबिक कैंसर की दवाएं, शुगर की दवाइयां, ईवी बैटरी, बायोमास सीएनजी, कपड़े, जूते और माइक्रोवेव ओवन जैसे जरूरी और घरेलू उपयोग के सामान सस्ते होंगे। इसके अलावा विदेश यात्रा और विमानों के ईंधन से जुड़े शुल्कों में राहत से हवाई सफर भी अपेक्षाकृत किफायती हो सकता है। सरकार का कहना है कि इन कदमों से स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

वहीं दूसरी ओर शराब, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला जैसे उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे ये और महंगे हो जाएंगे। इसके साथ ही खनिज, स्क्रैप, ऑप्शन ट्रेडिंग, विदेशी परफ्यूम, लग्जरी घड़ियां और आयातित वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा तय माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन वस्तुओं पर कर बढ़ाने का उद्देश्य गैर-जरूरी और विलासिता आधारित खपत को हतोत्साहित करना है।

विशेषज्ञों के अनुसार बजट 2026 का फोकस साफ है–जरूरतों को सस्ता, शौक को महंगा। इससे आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी, जबकि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुओं की खपत पर अंकुश लगेगा। कुल मिलाकर बजट ने संतुलन साधते हुए जनता की प्राथमिक जरूरतों को केंद्र में रखा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग–534 पर रात्रिकालीन यातायात प्रतिबंध, वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील

पथ प्रवाह, पौड़ी। राष्ट्रीय राजमार्ग-534 (पूर्व एनएच-119) पर गुमखाल से सतपुली के मध्य किमी 175 से 196 तक चल रहे मार्ग सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य के चलते यातायात व्यवस्था में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। उपजिलाधिकारी रेखा आर्य ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से 02 फरवरी से 05 फरवरी, 2026 तक प्रतिदिन रात्रि 09 बजे से प्रातः 06 बजे तक उक्त मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दिन के समय यातायात परिस्थितियों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा हेतु वैकल्पिक मार्ग के रूप में सतपुली-काण्डाखाल-सिसल्डी-डेरियाखाल मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गयी है। निर्माण स्थल पर आवश्यक सुरक्षा संकेतक, बैरिकेडिंग एवं प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा आपातकालीन सेवाओं का संचालन सुचारु रखा जाएगा। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि वे अस्थायी असुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। यह व्यवस्था भविष्य में सुरक्षित एवं सुगम सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश बजट का देखा लाइव प्रसारण

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

हरिद्वार शहर व्यापार मंडल मध्य हरिद्वार के अध्यक्ष मृदुल कौशिक के संयोजन में और भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा की अध्यक्षता में केंद्रीय बजट के लाइव प्रसारण को कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने एक साथ बैठकर देखा। चंद्राचार्य चौक रानीपुर मोड पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने व्यापारी भाइयों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बजट का सीधा प्रसारण देखा।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि यह बजट बहुत ही संतुलित और राष्ट्र को विकास की ओर ले जाने वाला है। इस बजट से विकसित भारत बनने का रास्ता निकलता है। उन्होंने कहा कि इस बजट में संतुलित विकास की नींव का स्ट्रक्चर मजबूत होगा। यह बजट नौजवानों, किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में नौजवानों, किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग के लिए बहुत कुछ प्रावधान रखे गए हैं। जिससे उनकी आजीविका को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर नगर विधायक मदन कौशिक ने कहा कि यह बजट भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेरहवां बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवीं बार लगातार बजट पेश कर एक मिसाल कायम की है। इस बजट से हर वर्ग संतुष्ट है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जन-जन तक जाकर इस बजट के विषय में जनता को अवगत कराए।

हरिद्वार ने हॉकी प्रतियोगिता के कड़े मुकाबले में चम्पावत को 2—0 से हराया

पथ प्रवाह, हरिद्वार। खेल निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून, जिला प्रशासन हरिद्वार के मार्गदर्शन एवं जिला खेल कार्यालय के तत्वावधान में आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय हॉकी अण्डर-18 प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे है। इस प्रतियोगिता में राज्य के 11 जनपदों सहित 13 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं।

प्रतियोगिता के तीसरे दिन के मैचों में पहला मैच जनपद हरिद्वार (बी) एवं जनपद चम्पावत के मध्य खेला गया जिसमें हरिद्वार (बी) की टीम जनपद चम्पावत को 2-0 से हराकर विजयी रही।

प्रतियोगिता का दूसरा मैच जनपद देहरादून एवं जनपद हल्द्वानी के मध्य खेला गया जिसमें जनपद देहरादून की टीम जनपद हल्द्वानी को 10-0 से हराकर विजयी रही। प्रतियोगिता का तीसरा मैच जनपद हरिद्वार (ए) एवं जनपद उधमसिंह नगर के मध्य खेला गया जिसमें जनपद हरिद्वार (ए) ने जनपद उधमसिंह नगर को 4-0 से हराकर विजयी रही। प्रतियोगिता का चौथा मैच जनपद नैनीताल एवं जनपद पौडी के मध्य खेला गया जिसमें जनपद नैनीताल की टीम जनपद पौड़ी को 6-0 से हराकर विजयी रही। प्रतियोगिता का पाँचवा मैच जनपद हरिद्वार (बी) एवं जनपद देहरादून के मध्य खेला गया जिसमें जनपद हरिद्वार (बी) की टीम जनपद देहरादून को 3-2 से हराकर विजयी रही। आज जनपद हरिद्वार (ए) एवं जनपद देहरादून के मध्य पहला, तथा जनपद हरिद्वार (बी) एवं जनपद उधमसिंह नगर के मध्य दूसरा सेमीफाईनल मैच खेला जायेगा। निर्णायकों की भूमिका में अमित कटारिया, अमित नेगी, हरीश नेगी, महिमा भण्डारी, परमिता गौतम, सौरभ पटवाल रहे। इस अवसर पर शबाली गुरुंग जिला क्रीडा अधिकारी हरिद्वार, प्रजापति कुकरेती मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विक्रम सिंह कनिष्ठ सहायक, शिखा बिष्ट, सहायक प्रशिक्षक, दीपक चन्द्र जोशी, सहायक प्रशिक्षक, मंगल सिंह, शुभम बोहरा, अभिषेक मुरारी, अनुराग सिंह धमान्दा, एंव अनेक खेलप्रेमी उपस्थित रहे।

बहादराबाद पुलिस ने खोली 10 व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के नेतृत्व में थाना बहादराबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गोकशी, चोरी, लूट, लड़ाई-झगड़ा, अवैध शराब/अवैध शस्त्र एवं मादक पदार्थों से जुड़े आदतन 10 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार द्वारा जनपद में गोकशी, मादक पदार्थों/मादक द्रव्यों की तस्करी, अवैध शस्त्र, अवैध शराब, लूट, चोरी, नकबजनी, लड़ाई-झगड़ा, बलवा कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले आदतन अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। थाना बहादराबाद पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के ऐसे 10 आदतन अपराधियों के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खोली गई है, जो उपरोक्त अपराधों में संलिप्त रहे हैं। इन सभी हिस्ट्रीशीटरों की प्रत्येक गतिविधि पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी तथा नियमानुसार प्रत्येक माह थाने में परेड कराई जाएगी, ताकि क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर एवं मॉडल जनपद बनाने की दिशा में तीन माह से स्वच्छता अभियान

मुख्यमंत्री के निर्देश व जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में स्वच्छता को जन–आंदोलन बनाने का प्रयास

पथ प्रवाह, हरिद्वार

तीर्थ नगरी हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर, क्लीन एवं मॉडल जनपद के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में तथा जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जनपद में विगत तीन माह से व्यापक स्वच्छता अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को केवल प्रशासनिक कार्यक्रम न बनाकर जन-आंदोलन के रूप में स्थापित करना है।

इसी क्रम में रविवार को मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा के नेतृत्व में बहादराबाद क्षेत्र में जनसहभागिता के साथ वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों तथा विभिन्न विभागों के

अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

स्वच्छता अभियान के दौरान बहादराबाद क्षेत्र में शिवालिक नगर मोड़, गंग नगर मोड़ से बहादराबाद चौराहे तक मुख्य मार्गों के दोनों ओर, सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियों एवं आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सफाई की गई। साथ ही क्षेत्र की सभी पंचायतों में भी सफाई अभियान संचालित कर स्वच्छता का संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने कहा कि स्वच्छता अभियान विगत दो माह से निरंतर संचालित हो रहा है और अब यह तीसरे माह में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वच्छता केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। अभियान के दौरान मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई, जिससे लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना और अधिक सुदृढ़ हो सके।

इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, नोडल स्वजल चंद्रकांत मणि त्रिपाठी, ग्राम प्रधान मोहित चौहान, एडीओ पंचायत राजेंद्र बिष्ट, स्वयंसेवी संस्थाएं, एनआरएलएम समूह की महिलाएं, महिला मंगल दल, आईटीसी सुनहरा कल की टीम, शिवालिक नगर पालिका के समस्त कर्मचारी, सिडकुल के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एवं जिलास्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

एक नजर

संत रविदास शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प, एक की मौत

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जनपद के भगवानपुर कोतवाली क्षेत्र में संत रविदास शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में हिसंक झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। इस दौरान फायरिंग किये जाने की भी जानकारी सामने आयी। इस घटना में फायरिंग के दौरान तीन लोगों के गोली लगने से घायल होने की जानकारी सामने आयी है। जिसमें एक की मौत होने की खबर भी आई, हालांकि समाचार लिखे जाने तक इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक भगवानपुर क्षेत्र के एक गांव में आज संत रविदास जयंती पर शोभायात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान दो गुटों में विवाद हो गया। वहां लोग वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह विवाद को शांत कराया, किंतु शोभायात्रा समाप्ति के बाद विवाद में पुनः हिंसक रूप ले लिया। दो गुट आमने-सामने आ गए, जिसके चलते जमकर पथराव और फायरिंग हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण किया। घटना को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। एसएसपी ने दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

छह दिन से लापता युवक का जंगल में मिला शव, हत्या की आशंका

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कोतवाली लक्सर क्षेत्र के गांव कंकरखाता से पिछले 6 दिनों से लापता युवक का शव रविवार को मोहम्मदपुर कुन्हारी गांव के जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को हत्या से जोड़कर देख रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंकरखाता गांव निवासी सन्नी उर्फ पोल्ला (22 वर्ष) पुत्र मानसिंह बीती 27 जनवरी को अचानक घर से लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी आसपास के गांवों और रिश्तेदारियों में काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद परिजनों ने रायसी चौकी पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी थी। रविवार को मोहम्मदपुर कुन्हारी गांव के जंगल में एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर लक्सर कोतवाली के एसएसआई लोकपाल परमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। बाद में मौके पर पहुंचे सन्नी के परिजनों ने शव की पहचान सन्नी के रूप में की। मृतक के परिजनों ने सन्नी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई लेखराज ने बताया कि 27 जनवरी को गांव के ही कालू, रोहित, राजा, सौरभ और बंटी सन्नी को अपने साथ लेकर गए थे। लेखराज का आरोप है कि मोबाइल से जुड़े किसी विवाद के चलते सन्नी की हत्या की गई है। इस संबंध में लक्सर कोतवाली के एसएसआई लोकपाल परमार ने बताया कि मोहम्मदपुर कुन्हारी गांव के जंगल में मिला शव कंकरखाता निवासी सन्नी उर्फ पोल्ला का ही है, जो पिछले छह दिनों से लापता था। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

हरिद्वार पुलिस ने पढ़े-लिखे मोबाइल स्नैचरों के गैंग का किया पर्दाफाश

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

थाना सिडकुल क्षेत्र में लगातार हो रही मोबाइल झपटमारी की घटनाओं से आमजन में व्याप्त दहशत को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल के निर्देशानुसार सिडकुल पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए पढ़े-लिखे झपट्टमार गैंग का खुलासा किया गया है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन शातिर मोबाइल स्नैचरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी व छीने गए कुल 06 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 31 जनवरी 2026 को की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने पाया कि गिरफ्तार आरोपी मेट्रिक एवं ग्रेजुएट हैं तथा वर्तमान में सिडकुल स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी नौकरी की आड़ में मोबाइल झपटमारी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। बरामद 06 मोबाइल फोन में से 03 मोबाइल थाना सिडकुल में पंजीकृत मु0अ0सं0- 37/2026, 40/2026 एवं 41/2026 (धारा 304(2) बीएनएस) से संबंधित हैं। बरामदगी के आधार पर अभियोगों में धारा 317(2), 3(5) बीएनएस तथा 35/106 ब्रह्मस्स की बढ़ोत्तरी की गई है। शेष 03 मोबाइल धारा 35/106 ब्रह्मस्स के अंतर्गत

बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

दीपक पुत्र रामचन्द्र, निवासी राजा बिस्कुट चौक, थाना सिडकुल, हरिद्वार।

मूल निवासी - ग्राम घंघेडी, थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर (उ.प्र.), उम्र 24 वर्ष।

अभिनव पुत्र हुकम सिंह, निवासी महादेवपुरम कॉलोनी, थाना सिडकुल, जनपद हरिद्वार। मूल निवासी - ग्राम इब्राहिमपुर, थाना धामपुर, जनपद बिजनौर (उ.प्र.), उम्र 21 वर्ष।

दीपू कुमार पुत्र बिश्मबर, निवासी महादेवपुरम, थाना सिडकुल, जनपद हरिद्वार। मूल निवासी - ग्राम हरिपुर गोकल, थाना अफजलगढ़, जनपद बिजनौर (उ.प्र.), उम्र 25 वर्ष।

पुलिस टीम

थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा, थाना सिडकुल, अ0उ0नि0 अनिल कुमार

अ0उ0नि0 संजय चौहान, हे0का0 155 संजय सिंह, थाना सिडकुल, हे0का0 217 देशराज, थाना सिडकुल, का0 336 कुलदीप, थाना सिडकुल, का0 930 कुलदीप, थाना सिडकुल, का0 226 प्रमोद गोस्वामी, का0 717 प्रदीप

का0 685 गजेन्द्र, थाना सिडकुल

संत रविदास जी के समानता, भाईचारे और मानवतावादी संदेश को अपनायें समाज: आदेश चौहान

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

संत शिरोमणि गुरू रविदास जी की 649वीं जयंती पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान ज्वालापुर, जगजीतपुर, रावली महदूद, सलेमपुर बीएचईएल, बहादराबाद सहित क्षेत्र के विभिन्न रविदास मंदिरों में पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए।

इस दौरान संत श्री रविदास महाराज जी की जयंती के पावन अवसर पर उन्हें नमन करते हुए उनके समानता, भाईचारे और मानवतावादी संदेशों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने सभी से समाज में सद्भाव बढ़ाने और गुरु रविदास जी के विचारों पर चलने का संकल्प लेने की अपील की। साथ ही सामाजिक एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी ने जातिवाद से ऊपर उठकर मानव प्रेम, समानता और एकता का जो संदेश दिया वह आज भी प्रासंगिक है । उनका यह कथन कि मन चंगा तो कटौती में गंगा हमें आत्मनिर्भरता और सच्चाई का मार्ग दिखाता है। इस अवसर पर नगरपालिका शिवालिकनगर सांसद प्रतिनिधि अतुल वशिष्ठ, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि चमन चौहान, हंसराज कटारिया, संजय सिंह, प्रिंस लोहट, रजनी वर्मा, मनोज प्रालिया, अजय

बबली, विकास सिंह, प्रधान प्रमोद पाल, सभासद गरिमा सिंह, सतपाल सिंह, राकेश कुमार, ऋषिपाल, सतीश मेघराज, धर्मेन्द्र, अमित, भूषण, सुखपाल, पवन वर्मा, सुनील कुमार, राजकुमार, संजय, सोनू, मोहित आदि उपस्थित रहे।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए 2,103 करोड़ रुपये का आवंटन

नयी दिल्ली। वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए 2,103 करोड़ रुपये का आवंटन का प्रस्ताव है, जिसमें 2,058 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय और 45 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव है। खास बात यह है कि इस बजट का 42 प्रतिशत यानी 890 करोड़ रुपये एयर इंडिया से संबंधित देनदारियों और प्रतिबद्धताओं पर खर्च किया जायेगा जिसे सरकार ने टाटा समूह को बेच दिया था। सार्वजनिक कंपनी रहते हुए एयर इंडिया के ऋणों को खरीदने के लिए बनी विशेष उद्देश्य वाली कंपनी एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड को उस ऋण की भरपाई के लिए 758.39 करोड़ रुपये दिये जाने का प्रस्ताव है।

बजट में एयर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए भी 132 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छोटे और मझौले शहरों तक संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू की गयी क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) उड़ान के लिए आवंटन बढ़ाकर 550 करोड़ रुपये किया गया है। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 435 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। आरसीएस के तहत एक तरफ नियमित उड़ान शुरू करने के लिए छोटे हवाई अड्डों को विकसित करने पर सरकार खर्च करती है और दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के राज्यों में विमानन अवसंरचना के विकास के लिए सरकार समर्थन प्रदान करती है।

संपादकीय

बजट 2026-27: विकसित भारत पर राजनीतिक मुहर

केंद्रीय बजट 2026-27 सिर्फ़ आर्थिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही राजनीति की दिशा और मंशा का स्पष्ट राजनीतिक वक्तव्य है। जिस समय विपक्ष सरकार को महंगाई, बेरोज़गारी और सामाजिक असंतोष के सवालों पर घेरने की कोशिश कर रहा था, उसी समय यह बजट तथ्यों, आंकड़ों और नीतिगत स्पष्टता के साथ उन आरोपों का सीधा जवाब बनकर सामने आया है।

रविवार को बजट प्रस्तुत किया जाना प्रतीकात्मक भी है और संदेशात्मक भी–यह बताता है कि सरकार चुनावी गणनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेने का साहस रखती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह सरकार की आर्थिक नीति में निरंतरता और राजनीतिक स्थिरता का प्रमाण भी है। यह उस दौर में खास महत्व रखता है जब विपक्ष नेतृत्वहीनता और नीति-विहीन आलोचना में उलझा दिखता है।

राजकोषीय घाटे को 4.3 प्रतिशत तक लाने की स्पष्ट रूपरेखा सरकार की वित्तीय विश्वसनीयता को मजबूत करती है। यह उन राजनीतिक आरोपों को भी कमजोर करती है, जिनमें कहा जाता है कि सरकार लोकलुभावन योजनाओं के लिए देश की अर्थव्यवस्था से समझौता कर रही है। बजट यह संदेश देता है कि गरीब कल्याण और वित्तीय अनुशासन–दोनों साथ चल सकते हैं, बशर्ते राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत हो।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह बजट सीधे उन वर्गों को साधता है जो लंबे समय से सत्ता की दिशा तय करते आए हैं–महिलाएँ, ग्रामीण मतदाता, मध्यम वर्ग और युवा। 'लखपति दीदी', महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण स्टार्टअप्स और रोजगार सृजन जैसे प्रावधान केवल योजनाएँ नहीं, बल्कि 2029 के राजनीतिक विमर्श की बुनियाद हैं। विपक्ष के पास इन मुद्दों का कोई वैकल्पिक रोडमैप नज़र नहीं आता।

उत्तराखंड जैसे सीमांत और पर्वतीय राज्यों का बजट भाषण में विशेष उल्लेख राजनीतिक रूप से भी अहम है। वर्ल्ड क्लास ट्रैकिंग, दुर्गम मार्गों का विकास और एडवेंचर टूरिज्म के ज़रिए सरकार ने साफ कर दिया है कि विकास अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहेगा। यह उस विपक्षी नैरेटिव को भी चुनौती देता है, जिसमें पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों की उपेक्षा का आरोप लगाया जाता रहा है।

वैश्विक दबावों–चाहे वह व्यापारिक टैरिफ हों या भू-राजनीतिक तनाव–के बीच भारत का संतुलित आर्थिक रुख सरकार की राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। जब विपक्ष बाहरी घटनाओं को सरकार की विफलता के रूप में पेश करने की कोशिश करता है, तब यह बजट आत्मनिर्भर भारत के राजनीतिक आत्मविश्वास को रेखांकित करता है।

बजट 2026-27 आर्थिक दस्तावेज़ से कहीं अधिक एक राजनीतिक घोषणा-पत्र जैसा है–जो यह स्पष्ट करता है कि मोदी सरकार विकास की राजनीति को अपनी सबसे बड़ी चुनावी पूंजी मानती है। अब विपक्ष के सामने केवल आलोचना नहीं, बल्कि ठोस विकल्प देने की चुनौती है। क्योंकि इस बजट ने साफ कर दिया है–राजनीति अब नारों से नहीं, नीतियों और नतीजों से तय होगी।

आर्द्रभूमियाँ-प्रकृति का कवच और मानव अस्तित्व की कुंजी

सुनील कुमार महला

हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस (वर्ल्ड वैटलैंड्स डे) मनाया जाता है। वास्तव में, यह दिवस 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुए रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) का संरक्षण और उनका विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि आर्द्रभूमियाँ (वैटलैंड्स) धरती के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं। ये वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पानी और मिट्टी आपस में मिलते हैं, और जहाँ पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ महीनों तक जलभराव रहता है, जैसे कि झीलें, तालाब, दलदल, मैंग्रोव, नदियों के किनारे के क्षेत्र आदि।आर्द्रभूमियों को धरती के गुर्दे कहा जाता है, क्योंकि ये पानी को स्वच्छ करने का काम करती हैं। ये जल में मौजूद प्रदूषकों, तलछट और अतिरिक्त पोषक तत्वों को सोख लेती हैं, जिससे भूजल साफ और सुरक्षित रहता है। इन्हें जैविक सुपरमार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अत्यंत विस्तृत खाद्य जाल (फूड वेब) पाया जाता है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि पृथ्वी की लगभग 40% जैव विविधता आर्द्रभूमियों पर निर्भर है, जबकि ये पृथ्वी की सतह के केवल 6% क्षेत्र में ही फैली हुई हैं। आर्द्रभूमियाँ स्पंज की तरह कार्य करती हैं। बारिश के समय ये अतिरिक्त पानी को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं और इस तरह बाढ़ की तीव्रता को कम करती हैं। साथ ही, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर मिट्टी में जमा करती हैं, और कई बार जंगलों से भी अधिक प्रभावी ढंग से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करती हैं। इसी कारण इन्हें कार्बन सिंक भी कहा जाता है।विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही, इनके संरक्षण और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना, ताकि ये प्राकृतिक प्रणालियाँ लंबे समय तक बनी रहें। इस दिवस का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय समुदायों और नीति निर्माताओं को जोड़ना है, ताकि आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास किए जा सकें।हर वर्ष इस दिवस के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है।2025 की थीम थी-हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण। इस वर्ष यानी कि 2026 की थीम है-आर्द्रभूमियाँ और पारंपरिक ज्ञानः सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। वास्तव में, यह थीम यह दर्शाती है कि पारंपरिक और स्थानीय समुदायों का ज्ञान आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है और आज भी उनकी संस्कृति व जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यदि हम यहां पर आर्द्रभूमियों के महत्व की बात करें तो ये पानी का नियमन और शुद्धिकरण करती हैं,जैव विविधता का घर हैं, आजीविका का स्रोत हैं (मछली पकड़ना, कृषि, पर्यटन और रोजगार),तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक हैं। बहरहाल, यदि वैश्विक आँकड़ों पर नज़र डालें, तो विश्व में कुल 2,520 रामसर साइट्स हैं, जो लगभग 2.53 करोड़ हेक्टेयर (25.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र में फैली हुई हैं तथा अब तक 172 से अधिक देशों ने रामसर कन्वेंशन को अपनाया है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षित पारिस्थितिक तंत्र नेटवर्क माना जाता है। भारत की बात करें तो यहाँ 98 रामसर साइट्स हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के रूप में मान्यता मिली है। हाल ही में पटना बर्ड सैंक्चुअरी और छारी-धंध बर्ड सैंक्चुअरी को इस सूची में जोड़ा गया है। ये सभी मिलकर लगभग 13.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती हैं।

बजट 2026-27 : लोकलुभावन वादों से दूर, राहत और मायूसी का मिश्रण

योगेश कुमार गोयल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 को एक ओर जहां सरकार के घटक दलों द्वारा विकसित भारत का बजट और बदलते भारत की राजनीतिक-आर्थिक प्राथमिकताओं तथा सरकार की दीर्घकालिक सोच का आईना बताया गया है, वहीं विपक्ष द्वारा इसे पूरी तरह दिशाहीन बजट करार दिया गया है। वैसे निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार बजट पेश कर संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। सवाल यह नहीं है कि बजट कितना बड़ा है या कितने नए आंकड़े पेश किए गए हैं बल्कि यह है कि क्या यह बजट महंगाई से जूझ रहे आम नागरिक के वर्तमान को कुछ राहत देता है और भविष्य के लिए भरोसेमंद आधार तैयार करता है? बजट के तमाम महत्वपूर्ण प्रावधानों का आकलन किया जाए तो यह बजट विकास, निवेश, बुनियादी ढ़ांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की स्पष्ट झलक तो दिखाता है लेकिन इसके साथ ही इसमें कई ऐसे खाली स्थान भी हैं, जो आम आदमी और विशेषकर किसान, निम्न आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए निराशा पैदा करते हैं। सरकार ने इस बार तात्कालिक लोकलुभावन उपायों से दूरी बनाते हुए दीर्घकालिक क्षमता निर्माण पर जोर दिया है। यह दृष्टिकोण आर्थिक रूप से समझदारी भरा हो सकता है लेकिन लोकतंत्र में बजट का मूल्यांकन केवल भविष्य के सपनों से नहीं, वर्तमान की चुनौतियों से भी होता है।

शिक्षा और रोजगार को जोड़ने वाला 'एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट' मॉडल सरकार की उस सोच को सामने लाता है, जो कक्षा और कार्यस्थल के बीच की खाई को पाटने का दावा करती है। पहली नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए 15,000 रुपये का डीबीटी बोनस और एक करोड़ इंटर्नशिप की घोषणा निश्चित रूप से आकर्षक लगती है। यह कदम युवाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में सकारात्मक है। लेकिन यहां भी सबसे बड़ा प्रश्न क्रियान्वयन का है। क्या ये इंटर्नशिप वास्तविक कौशल और स्थायी रोजगार की ओर ले जाएंगी या फिर यह योजना सस्ते श्रम तक सीमित रह जाएगी? भारत पहले भी कई बार योजनाओं के आकर्षक नाम और बड़े लक्ष्यों के बावजूद जमीनी स्तर पर कमजोर क्रियान्वयन का अनुभव कर चुका है।

'स्किल इंडिया 2.0' के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती तकनीकों को क्षेत्रीय भाषाओं में सिखाने की योजना डिजिटल डिवाइड को कम करने की दिशा में अहम कदम है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी युवाओं के लिए यह तकनीकी दुनिया में प्रवेश का द्वार खोल सकता है लेकिन प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और उद्योग-सहयोग के बिना यह पहल भी सीमित असर तक सिमट सकती है। शिक्षा बजट को लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव सराहनीय है लेकिन बढ़ती छात्र संख्या, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और शोध की जरूरतों के सामने यह राशि अपर्याप्त प्रतीत होती है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट राहत और मायूसी का मिश्रण है। आयकर दरों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन आयकर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में घोषणा अवश्य की गई है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, कर व्यवस्था को जटिल छूटों के जाल से निकालकर सरल और पारदर्शी बनाना, ताकि उपभोग बढ़े और अर्थव्यवस्था में मांग का संचार हो। यह दृष्टिकोण आर्थिक सुस्ती के दौर में उपयोगी हो सकता है।

सरकार ने कुछ चुनिंदा वस्तुओं और क्षेत्रों में कर कटौती कर राहत देने की कोशिश की है। कैंसर और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं का सस्ता होना निसंदेह करोड़ों परिवारों के लिए जीवनरक्षक कदम है। मोबाइल फोन, ईवी बैटरी और सौर पैनलों पर रियायतें हरित ऊर्जा और डिजिटल इंडिया को गति देने के साथ-साथ तकनीक को आम आदमी की पहुंच में लाने का प्रयास हैं। जूते, कपड़े और कुछ घरेलू उपकरणों के सस्ते होने से मध्यमवर्गीय खपत में हल्की तेजी आ सकती है लेकिन दूसरी ओर शराब, खनिज और स्क्रैप पर बढ़े शुल्क से उत्पादन लागत बढ़ने और अंततः उपभोक्ता कीमतों पर असर पड़ने की आशंका भी बनी हुई है। सबसे बड़ा झटका शेयर बाजार में देखने को मिला। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर बढ़े टैक्स ने खुदरा निवेशकों की धारणा को कमजोर किया और बजट के दौरान बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे यह संदेश गया कि सरकार सट्टात्मक गतिविधियों पर सख्ती चाहती है लेकिन इसके दुष्परिणाम अल्पकाल में निवेशकों और बाजार की स्थिरता पर पड़े। यह बजट महंगाई और निवेश के मोर्चे पर एक तरह का विरोधाभास प्रस्तुत करता है, एक ओर खपत बढ़ाने की कोशिश, दूसरी ओर निवेश भावना को झटका।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर ?12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय सरकार की विकास रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ है। सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जिनमें मुंबई-पुणे और दिल्ली-वाराणसी जैसे मार्ग शामिल हैं, भारत की कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास की तस्वीर बदल सकते हैं। बेहतर परिवहन से उद्योग, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और रियल एस्टेट को नई गति मिल सकती है। टियर-2 और टियर-3 शहरों पर फोकस शहरीकरण के असंतुलन को सुधारने की दिशा में सही कदम है। हालांकि, बुनियादी ढ़ांचे पर खर्च का लाभ आम आदमी तक पहुंचने में समय लगता है और तात्कालिक रूप से निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी महंगाई का दबाव बढ़ा सकती है। एमएसएमई और व्यापार जगत के लिए बजट में नई संजीवनी दिखाई देती है। 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड छोटे उद्यमों को पूंजी की कमी से उबार सकता है। महिलाओं के लिए मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना महिला उद्यमिता को वास्तविक आर्थिक ताकत देने की दिशा में अहम कदम है। टेक्निकल टेक्सटाइल पर विशेष फोकस भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थान दिला सकता है और 'मेक इन इंडिया' को व्यावहारिक आधार दे सकता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह बजट ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योंकि पहली बार कंटेंट क्रिएटर्स और क्रिएटिव इकोनॉमी को औपचारिक मान्यता दी गई है। 'रील' और 'रियल' इकोनॉमी के बीच की दीवार लगभग गिर चुकी है। डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, एनीमेशन और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को एमएसएमई जैसा दर्जा मिलने से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं।

विकसित भारत की उड़ान : बजट 2026 के आर्थिक संकल्प

ललित गर्ग

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत नवीन केंद्रीय बजट को यदि समग्र दृष्टि से देखा जाए तो यह केवल एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के स्वप्न की ठोस आधारशिला के रूप में सामने आता है। यह बजट उस रिफॉर्म एक्सप्रेस की तरह है जो बीते वर्षों में चली आर्थिक सुधारों की पटरियों पर तेज़ गति से दौड़ते हुए अब भारत को उच्च विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता की नई ऊँचाइयों की ओर ले जाने का दावा करता है। तुलनात्मक, विवेचनात्मक और समीक्षात्मक दृष्टि से यह बजट पूर्ववर्ती बजटों की निरंतरता को बनाए रखते हुए कई नए आयाम भी जोड़ता है, जो इसे ऐतिहासिक और भविष्यगामी बनाते हैं। पिछले कुछ वर्षों के बजटों की तुलना में यह बजट अधिक आत्मविश्वास के साथ सामने आता है। महामारी, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बीच भारत ने जिस आर्थिक मजबूती का प्रदर्शन किया है, उसका आत्मविश्वास इस बजट में स्पष्ट झलकता है। जहां पूर्व बजटों में संकट प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को संभालने पर अधिक जोर था, वहीं यह बजट विकास की ऊंची उड़ान के लिए रनवे तैयार करता दिखता है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का मंत्र यहां नारे से आगे बढ़कर नीतिगत संरचना का रूप लेता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट की दृष्टि विशेष रूप से विवेचनात्मक है। चिकित्सा अवसंरचना के विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और डिजिटल हेल्थ के माध्यम से गांव-गांव तक चिकित्सा सुविधाएं पहुँचाने की दिशा में किए गए प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सरकार स्वास्थ्य को केवल खर्च नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश मान रही है। यदि पिछले दशक के बजटों से तुलना की जाए तो स्वास्थ्य पर आवंटन और दृष्टिकोण दोनों में गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। यह बदलाव भारत को न केवल स्वस्थ समाज की ओर ले जाने वाला है, बल्कि उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि को भी दीर्घकाल में मजबूती देगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट की आत्मा दूरदर्शी है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़ी शिक्षा पर बल यह दर्शाता है कि सरकार भविष्य के भारत के लिए आज के युवाओं को तैयार करना चाहती है। पूर्ववर्ती बजटों में शिक्षा पर खर्च की चर्चा होती थी, लेकिन इस बजट में शिक्षा को रोजगार और नवाचार से जोड़ने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ यह बजट तुलनात्मक रूप से अधिक परिपक्व और व्यावहारिक प्रतीत होता है। विकास की दृष्टि से यह बजट 'इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस समावेशन' का मॉडल प्रस्तुत करता है। रेलवे कॉरिडोरों के विकास, लॉजिस्टिक्स को सशक्त बनाने, सड़क, बंदरगाह और शहरी अवसंरचना में निवेश को जिस तरह प्राथमिकता दी गई है, वह भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत हिस्सा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सात रेलवे कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा केवल परिवहन सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलन का माध्यम भी है। यदि इसे पिछले बजटों से जोड़कर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि सरकार अब बुनियादी ढांचे को विकास का इंजन मानकर लगातार गति दे रही है। ग्रामीण भारत के संदर्भ में यह बजट विशेष उल्लेख के योग्य है। कृषि, ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई, किसान कल्याण और ग्रामीण उद्यमिता से जुड़े प्रावधान यह संकेत देते हैं कि गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मंशा केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। मेडिकल सुविधाओं, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता सुधरने की संभावना बढ़ती है। यह आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसमें गांव मजबूत होंगे तो देश स्वतः मजबूत होगा।

नारी शक्ति के सशक्तिकरण के संदर्भ में भी बजट का दृष्टिकोण तुलनात्मक रूप से व्यापक है। महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमिता, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विशेष प्रावधान यह दर्शाते हैं कि महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की भागीदार के रूप में देखा जा रहा है।

गरीबों और वंचित वर्गों के लिए लक्षित योजनाएं इस बजट को सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी संतुलित बनाती हैं। समीक्षात्मक रूप से देखा जाए तो यह बजट कल्याण और विकास के बीच संतुलन साधने का प्रयास करता है, जो किसी भी दीर्घकालिक आर्थिक नीति की अनिवार्य शर्त है। युवाओं के लिए यह बजट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

एक नजर

केंद्रीय बजट 2026 : कर कानूनों में कई चूक अब नहीं अपराध

पथ प्रवाह, नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026 में करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आयकर और विदेशी संपत्ति से जुड़े कई प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। अब कई मामलों में आपराधिक कार्रवाई की जगह केवल जुर्माना भरकर मामला निपटाया जा सकेगा। बजट प्रस्तावों के अनुसार, ऑडिट न कराना, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट में चूक या वित्तीय जानकारी देने में गलती को अब अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसके अलावा दस्तावेज उपलब्ध न कराना या वस्तु के रूप में भुगतान पर टीडीएस न काटना भी अब आपराधिक अपराध नहीं रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि छोटे और तकनीकी मामलों में अब केवल आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जबकि गंभीर मामलों में अधिकतम सजा की अवधि को घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है। साथ ही अदालत को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस सजा को भी जुर्माने में बदल सके। बजट में विदेशी संपत्ति से जुड़े मामलों में भी बड़ी राहत दी गई है। 20 लाख रुपये से कम की विदेशी संपत्ति घोषित न करने पर अब 1 अक्टूबर 2024 से कोई दंड या आपराधिक केस दर्ज नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे ईमानदार करदाताओं को अनावश्यक कानूनी झंझट से राहत मिलेगी और टैक्स अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इन प्रावधानों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा और कर प्रणाली अधिक सरल व करदाता-हितैषी बनेगी।

गंगा में प्रवाहित हो रहे 14 भवनों का ग्रे-वाटर किया गया बंद, 02 नालियां टैप

पथ प्रवाह, देहरादून। जिला प्रशासन देहरादून ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सख्त कार्रवाई करते हुए बिना सीवर संयोजन के सीधे गंगा नदी में प्रवाहित हो रहे 14 भवनों के ग्रे-वाटर कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र की 02 नालियों की टैपिंग भी की गई है। विगत दिवस जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा ऋषिकेश स्थित चन्द्रेश्वर नगर के ढालवाला नाले का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नाले में अपशिष्ट जल (ग्रे-वाटर) प्रवाहित होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर निगम ऋषिकेश एवं जल संस्थान (गंगा), ऋषिकेश के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में जल संस्थान (गंगा), ऋषिकेश एवं नगर निगम ऋषिकेश द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि ढालवाला नाले के आसपास कुल 21 भवन स्थित हैं, जिनमें से 14 भवनों का ग्रे-वाटर सीधे नाले में प्रवाहित हो रहा था, जबकि शेष 07 भवनों का ग्रे-वाटर विधिवत सीवर लाइन से संयोजित पाया गया।

संयुक्त निरीक्षण के उपरांत जल संस्थान ऋषिकेश द्वारा ग्रे-वाटर प्रवाहित कर रहे 14 भवन स्वामियों को नोटिस जारी करते हुए मौके पर ही उनके भवनों से नाले में जाने वाले अपशिष्ट जल निकास को बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्र की 02 नालियों की भी टैपिंग की गई। इस कार्रवाई के बाद अब चन्द्रेश्वर नगर स्थित ढालवाला नाले में 14 भवनों एवं 02 नालियों से किसी भी प्रकार का ग्रे-वाटर प्रवाहित नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा गंगा स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रखी जाएगी।

आढ़ती के नौकर से ढाई लाख की लूट, भीड़ ने एक बदमाश पकड़ा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कोतवाली लक्सर क्षेत्र में लक्सर रोड पर बेगमपुर से आगे रविवार को दिनदहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई। आढ़ती के एक नौकर से चार बदमाशों ने ढाई लाख रुपये लूट लिए। वारदात के बाद मौके पर जुटी जनता ने साहस दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि उसके तीन साथी सवार होकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार लक्सर निवासी भूषण कुमार की आढ़त की दुकान है। रविवार को उन्होंने अपने नौकर रवि को सुल्तानपुर क्षेत्र में कलेक्शन के लिए भेजा था। दोपहर करीब तीन बजे रवि ढाई लाख रुपये लेकर वापस लक्सर लौट रहा था। जैसे ही वह बेगमपुर पार कर उदगांव के रास्ते के पास पहुंचा, तभी मोटरसाइकिल सवार चार बदमाशों ने उसे रोक लिया और रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। बैग छीनने का विरोध करने पर बदमाशों ने रवि के साथ मारपीट की। शोर-शराबा सुनकर आसपास के राहगीर मौके पर पहुंच गए। भीड़ को इकट्ठा होता देख तीन बदमाश बैग छीनकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए, जबकि एक बदमाश को पब्लिक ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और जमकर धुनाई के बाद सुल्तानपुर चौकी पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान साहिल पुत्र नफीस निवासी खड़ंजा कुतुबपुर के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने अपने फरार साथियों के नाम पुलिस को बताए हैं। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।

केन्द्रीय बजट में शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य व कौशल विकास पर विशेष फोकस: डॉ. धन सिंह रावत

देशभर के 15,000 स्कूलों व 500 कॉलेजों में स्थापित होंगी एवीजीसी कंटेंट लैब

पथ प्रवाह, देहरादून। उत्तराखण्ड के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास को सशक्त करने वाला दूरदर्शी, सर्वसमावेशी और भविष्यन्मुखी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिये तैयार करने के साथ-साथ भारत को वैश्विक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि केन्द्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिये 1,39,289 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.27 प्रतिशत अधिक है। बजट में पाँच यूनिवर्सिटी टाउनशिप की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जहाँ शोध, स्टार्ट-अप, नवाचार तथा इंडस्ट्री-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इन टाउनशिप्स का उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख और इंडस्ट्री-रेडी बनाना है।

उन्होंने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के सहयोग से देशभर के 15,000 विद्यालयों एवं 500 कॉलेजों में एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एवं कॉमिक्स) कंटेंट लैब स्थापित की जाएँगी। इसके साथ ही डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना से विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध होगी, जिससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनेंगे।

डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि बजट में प्रत्येक जनपद में एक-एक महिला छात्रावास (गर्ल्स हॉस्टल) की स्थापना का प्रावधान कर बालिका शिक्षा को नई मजबूती दी गई है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी।

कैबिनेट मंत्री ने इस जन-कल्याणकारी बजट के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्रीय बजट के अनुरूप राज्य स्तर पर ठोस एवं व्यवहारिक प्रस्ताव तैयार किये जाएँ, ताकि प्रदेशवासियों को इन योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

केंद्रीय बजट में तीन नए एम्स का ऐलान: डॉ. धन सिंह रावत

पथ प्रवाह, देहरादून

उत्तराखण्ड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने केंद्रीय बजट 2026-27 को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इस बजट में जन-स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में तीन नए एम्स, दो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों तथा एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल संस्थानों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिससे चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ मेडिकल शिक्षा को भी व्यापक विस्तार मिलेगा।

डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि बजट में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में पाँच क्षेत्रीय मेडिकल हब विकसित किए जाएंगे। ये मेडिकल हब अत्याधुनिक अस्पतालों, चिकित्सा शिक्षा एवं शोध सुविधाओं से युक्त इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंटर्स के रूप में कार्य करेंगे, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि डायबिटीज, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश में बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर दवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दवा उत्पादन में वृद्धि होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।

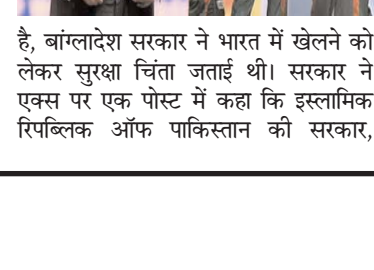

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्रीय बजट के अनुरूप राज्य स्तर पर ठोस एवं व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार किए जाएँ, ताकि उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और फार्मा क्षेत्र को नई दिशा मिल सके।

आदमपुर हवाई अड्डे को गुरु रविदास महाराज के नाम समर्पित

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आदमपुर हवाई अड्डे का नाम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के नाम पर समर्पित किया जाना उनके महान विचारों, सामाजिक चेतना और मानवता के प्रति समर्पण को सच्ची श्रद्धांजलि है। संत गुरु रविदास महाराज की जयंती के पावन अवसर पर लिया गया यह निर्णय न केवल अत्यंत सराहनीय है, बल्कि सामाजिक समरसता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल भी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि संत रविदास महाराज ने अपने जीवन और विचारों के माध्यम से समानता, करुणा, सेवा और मानव मात्र के सम्मान का संदेश दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त ऊँच-नीच, भेदभाव और असमानता के विरुद्ध आवाज़ उठाकर समतामूलक समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की, जो आज भी पूरी तरह प्रासंगिक और प्रेरणादायी है। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में महापुरुषों, संतों और समाज सुधारकों के विचारों को सम्मान देने की परंपरा निरंतर सशक्त हो रही है। आदमपुर हवाई अड्डे को संत गुरु रविदास महाराज के नाम से जोड़ना उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाने और नई पीढ़ी को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव को और अधिक मजबूत करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि संत गुरु रविदास महाराज के आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज समरसता, सद्भाव और सेवा के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ेगा।

बांग्लादेश के समर्थन में 15 फरवरी के मुकाबले का बॉयकॉट

नई दिल्ली। टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा। दोनों टीमें 15 फरवरी को कोलंबो में एक-दूसरे से भिडने वाली थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में एंट्री दी थी। इसके विरोध में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर दिया।

पाकिस्तान ने रविवार को घोषणा की कि वह टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करेगा। पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाने के बाद लिया है, बांग्लादेश सरकार ने भारत में खेलने को लेकर सुरक्षा चिंता जताई थी। सरकार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी वर्ल्ड टी-20 में हिस्सा लेने की मंजूरी देती है। हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने 26 जनवरी को प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन और भारत के खिलाफ मुकाबले को लेकर बाते हुईं। नकवी ने कहा था कि शुक्रवार या सोमवार तक आखिरी फैसला लिया जाएगा। अब रविवार को सरकार ने इस पर फैसला ले लिया।

प्रेम-प्रसंग बना हत्या की वजह, एम्स कर्मी महिला की गोली मारकर हत्या

पथ प्रवाह, ऋषिकेश।

कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र के शिवाजी नगर में शनिवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब किराये के मकान में रह रही एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान प्रीति रावत के रूप में हुई है, जो एम्स ऋषिकेश में सहायिका के पद पर कार्यरत थी और शिवाजी नगर, गली नंबर-11 में अकेले रहती थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी की रात्रि को कोतवाली ऋषिकेश को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने महिला को गोली मार दी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां महिला मृत अवस्था में मिली। घटना के संबंध में मृतका के पिता बच्चन सिंह रावत ने कोतवाली ऋषिकेश में लिखित तहरीर दी, जिसमें सुरेश गुप्ता पर उनकी पुत्री की गोली

मारकर हत्या करने का आरोप लगाया गया। तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा संख्या 49/26, धारा 103(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस की प्रारंभिक विवेचना में सामने आया कि प्रीति रावत का कुछ वर्ष पूर्व अपने पति से तलाक हो चुका था। कोरोना काल के दौरान वह सुरेश गुप्ता के ससुराल पक्ष की ऋषिकेश स्थित दुकान में काम करने आई थी, जहां दोनों के बीच परिचय बढ़ा और धीरे-धीरे प्रेम-संबंध स्थापित हो गए। इस संबंध की जानकारी सुरेश गुप्ता के परिवार को होने पर उसके और उसकी पत्नी के बीच लगातार विवाद होने लगे। स्थानीय लोगों ने कई बार समझौते का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ता गया।

बताया जा रहा है कि प्रीति से विवाह करने के लिए सुरेश गुप्ता ने करीब चार माह पूर्व आपसी सहमति से अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। इसके बाद प्रीति और उसके परिजनों द्वारा ऋषिकेश में संपत्ति खरीदने की बात कही गई, जिस पर सुरेश गुप्ता ने लक्सर, हरिद्वार स्थित अपनी पैतृक संपत्ति लगभग 35 लाख रुपये में बेच दी। हालांकि, उक्त राशि में ऋषिकेश में उपयुक्त मकान न मिल पाने के कारण दोनों के बीच तनाव बढ़ता चला गया, जिससे अभियुक्त अवसाद में चला गया।

पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रेम-प्रसंग, तलाक, संपत्ति बिक्री और लगातार बढ़ते मनमुटाव के चलते अभियुक्त द्वारा घटना को अंजाम देना प्रतीत हो रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जो उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस द्वारा मामले की गहन विवेचना करते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह खुद मौके पर पहुंचे और घटना की विस्तृत जानकारी हासिल की है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।

एक नजर

डोईवाला में श्रीमद् भागवत कथा में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

पथ प्रवाह, डोईवाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोईवाला में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक मूल्यों का सशक्त आधार है, जो मानव जीवन को सदाचार, सेवा और कर्तव्यबोध की प्रेरणा देती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज में नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ सामाजिक समरसता को भी मजबूत करते हैं। ऐसे आयोजन जनमानस को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विधायक प्रेमचंद अग्रवाल एवं उनके परिजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

पौड़ी एफसी और 12वीं गढ़वाल ने जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह

पथ प्रवाह, पौड़ी। पाबौ के खूंडेश्वर खेल मैदान में आयोजित स्वर्गीय विपिन सिंह व स्वर्गीय प्रताप सिंह राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहे। आज खेले गए दोनों क्वार्टर फाइनल मैचों में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर खेल प्रेमियों का खूब मनोरंजन किया। दिन का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला कंडोलिया एफसी और दिग्विजय क्लब कठुली के बीच खेला गया। मुकाबले में पौड़ी एफसी की ओर से 27वें मिनट में जर्सी नंबर 13 अमित ने शानदार गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। मैच के अंतिम क्षणों में दीपक ने एक और गोल कर पौड़ी एफसी की बढ़त को 2-0 कर दिया। इस तरह पौड़ी एफसी ने मुकाबला 2-0 से जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला 12वीं गढ़वाल और कोटली के बीच खेला गया, जिसमें 12वीं गढ़वाल ने एकतरफा प्रदर्शन किया। 7वें मिनट में अमित चौहान ने पहला गोल किया, जबकि 15वें मिनट में सुचारू डोभाल ने दूसरा गोल दागा। 29वें मिनट में अमित चौहान ने अपना दूसरा गोल कर स्कोर 3-0 कर दिया। दूसरे हाफ में प्रवेश ने 46वें मिनट में चौथा, विशाल ने 58वें मिनट में पांचवां और अंतिम समय में अभिषेक ने छठा गोल किया। इस तरह 12वीं गढ़वाल राइफल ने मुकाबला 6-1 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। मैच के मुख्य अतिथि आईएएस एवं पूर्व राज्य मंत्री सुंदर लाल मयाल रहे। विशिष्ट अतिथियों में एसबीआई पाबौ के शाखा प्रबंधक संजीव कुमार, वीरेंद्र सिंह नेगी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

खूंडेश्वर मैदान में रस्साकसी के रोमांचक मुकाबले, महिलाओं की भागीदारी ने बढ़ाया उत्साह

पथ प्रवाह, पौड़ी। पाबौ खेल समिति द्वारा खूंडेश्वर मैदान में आयोजित रस्साकसी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले बेहद रोमांचक और जोश से भरपूर रहे। प्रतियोगिता में ग्रामीण प्रतिभाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को रोमांचित कर दिया। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में कोटा, पाबौ, कोटली और धारकोट की टीमों ने जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में अपना-अपना स्थान पक्का किया। इन टीमों ने क्रमशः पाली, सेंजी, बिशल्ड और पाबौ बी टीम को कड़े मुकाबलों में पराजित किया। खूंडेश्वर मैदान में खेले गए इन मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों के उत्साह के साथ-साथ दर्शकों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। खास बात यह रही कि इस प्रतियोगिता में ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय और दमदार भागीदारी ने आयोजन को और भी खास बना दिया। कई महिला जनप्रतिनिधि अपनी-अपनी टीमों के समर्थन में मैदान में उतरकर उत्साह बढ़ाती नजर आईं, जिससे खेल का माहौल और जीवंत हो गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य भरत रावत

ने कहा कि पाबौ क्षेत्र में लंबे समय से ग्रामीण महिलाओं को मंच देने के उद्देश्य से इस प्रकार की खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर होते हैं, जहां वे अपने घरेलू कार्यों से समय निकालकर अपनी प्रतिभा और हुनर का प्रदर्शन कर सकती हैं। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और सामाजिक सहभागिता को भी मजबूती मिलती है। कार्यक्रम के दौरान आयोजन समिति के संरक्षक दुर्गेश प्रसाद थपलियाल, सुधीर रावत, सचिन रावत, मतवार सिंह चौहान, हरेंद्र कोहली, संदीप रावत सहित क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। आयोजन ने न केवल खेल भावना को प्रोत्साहित किया, बल्कि ग्रामीण समाज में एकजुटता और महिला सशक्तिकरण का भी मजबूत संदेश दिया।

पशु सखी योजना से स्वरोजगार का संबल, 22 पशु सखियों को स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में सशक्त बनाने तथा उन्हें लखपति दीदी की श्रेणी में अग्रसर करने के उद्देश्य से भारत सरकार की जनकल्याणकारी पशु सखी योजना के अंतर्गत विकास भवन परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान गंगोत्री विधानसभा विधायक सुरेश चौहान एवं मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह ने जनपद के विभिन्न विकास खंडों से चयनित 22 पशु सखी महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें पशु चिकित्सीय सेवाओं हेतु स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित किए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सा सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए यह भारत सरकार की अत्यंत लाभकारी योजना है। उन्होंने कहा कि पशु सखियों को पशुपालकों की समस्याओं का समाधान बेहतर उपचार, पशु चिकित्साधिकारियों के परामर्श एवं आपसी समन्वय के माध्यम से करना होगा, जिससे पशुओं से संबंधित समस्याओं में प्रभावी कमी लाई जा सके।

तत्पश्चात मुख्य विकास अधिकारी ने पशु सखियों को अपने दायित्वों के निर्वहन में कर्मठता, निष्ठा एवं समर्पण भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम स्तर पर स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने तथा पशुओं की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पशु सखी योजना

के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। एनआरएलएम एवं ग्रामोत्थान रीप परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला पशु सखी को 2500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

कार्यशाला में उपस्थित पशु सखियों को एनआरएलएम के तहत पशुलोक सेवा संस्थान, ऋषिकेश एवं कालसी में पशुओं से संबंधित टीकाकरण, समुचित जांच, गर्भाधान सहित विभिन्न चिकित्सीय सेवाओं का 17 दिवसीय गहन प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

इस अवसर पर परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अजय सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. हरि सिंह बिष्ट, मुख्य कृषि अधिकारी एस.एस. वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

एक नजर

बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नयी रफ्तार देने का महत्वाकांक्षी रोड़मैप : मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को विकसित भारत की ऊंची उडान का आधार बताते हुए कहा है कि इसमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नयी रफ्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी रोड़मैप प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट महत्वाकांक्षी भी है और देश की आकांक्षाओं को भी पूरा करता है। मोदी ने रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में बजट पेश किये जाने के बाद कहा कि यह बजट 2047 के विकसित भारत की ऊंची उडान का आधार है और इसमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नयी रफ्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी रोड़मैप प्रस्तुत किया गया है।

आर्थिक विशेषज्ञों की सुझाई चुनौतियों का भी बजट में नहीं है समाधान : कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि आम बजट 2026-27 में आर्थिक चुनौतियों से निपटने की ठोस पहल नहीं की गयी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा पेश चुनौतियों को जिस तरह से नजरअंदाज किया है उससे लगता है कि शायद उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ा ही नहीं है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने रविवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हर बजट की तरह इस बार के बजट पर भी सभी टिप्पणीकारों, लेखकों तथा अर्थशास्त्र के हर छात्र की पैनी नजर रही होगी और उन्होंने अवश्य संसद में वित्त मंत्री के भाषण को सुना होगा लेकिन उन्हें लगता है कि जो कुछ उन्होंने वित्त मंत्री के भाषण में सुना, उससे अवश्य ही स्तब्ध रह गये होंगे।

बजट सशक्त भारत की नींव को और मजबूत करने वाला : रेखा गुप्ता

नयी दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह बजट अवसरों का विस्तार करते हुए विकास को गति देने वाला है और आत्मनिर्भर सशक्त भारत की नींव को और मजबूत करता है। गुप्ता ने रविवार को पेश किये बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कहा ''बजट 2026-27 आज त्रिनगर में स्थानीय नागरिकों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ सुना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट अवसरों का विस्तार करता है, विकास को गति देता है और आत्मनिर्भर, सशक्त भारत की नींव को और मजबूत करता है।

बजट लोक-कल्याण, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करने वाला : नड्डा

नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रविवार को केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट को लोक-कल्याणकारी, सर्वसमावेशी और 'विकसित भारत' के लक्ष्य के प्रति संकल्पित देश के आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में स्थापित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है और देश की युवा शक्ति को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है।

हकीकत से दूर बजट में सुधार हुए हैं नजरअंदाज : राहुल

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बजट 2026-27 बुनियादी संकटों तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने से दूर है और इसमें सुधारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को पूरी तरह से नकार दिया गया है। गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को लोकसभा में पेश आम बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा 'बिना नौकरी के युवा, गिरती मैन्युफैक्चरिंग, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है। किसान संकट में, वैश्विक चुनौतियों और झटकों को नजरअंदाज कर दिया गया है। '

बजट दिशाहीन, चुनौतियों से निपटने का कोई प्रावधान नहीं : खरगे

नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से रविवार को पेश केन्द्रीय बजट को नीतिगत खालीपन, दूरदर्शिता तथा दिशाहीन करार देते हुए कहा है किआर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा 'बजट 2026-27 से साबित होता है कि इसमें देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के समाधान के लिए कोई उपाय नहीं किए गये हैं। बजट में चुनौतियों का ठोस समाधान करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिए गये हैं। सरकार का 'मिशन मोड' अब 'चुनौती मार्ग'बन चुका है और 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' किसी भी सुधार वाले स्टेशन पर रुकने से कतराता दिख रहा है। नतीजा यह है कि बजट में न तो कोई स्पष्ट नीतिगत विजन दिखता है और न ही कोई मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति। '

इंदौर सीवरेज घोटाले में फोटोकॉपी को सबूत मानने के फैसले को हाईकोर्ट ने किया रद्द

भोपाल। 2 साल पहले सामने आए करोड़ों रुपए के इंदौर सीवरेज घोटाले में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में पेश की गई फोटोकॉपी को सबूत मानने के फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस गजेंद्रसिंह की कोर्ट ने साफ कहा कि कानून की अनिवार्य शर्तें पूरी किए बिना फोटोकॉपी दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में नगर निगम ने 150 करोड़ के कथित घोटाले में अलग-अलग पांच से ज्यादा एफआइआर करवाई थी। निगम के ही कार्यपालन यंत्री अभय राठौर सहित अन्य को आरोपित बनाया गया था। इस घोटाले से जुड़े 17 मामलों में ट्रायल कोर्ट में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र सहित अन्य धाराओं में चालान के साथ 31 जुलाई 2025 को घोटाले से जुड़े दस्तावेजों की फोटोकॉपी दी गई थी। कोर्ट में एक आवेदन पुलिस की ओर से लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि मामले से जुड़े मूल दस्तावेज नगर निगम के आधिपत्य में थे जो गुम हो गए हैं। इनके मिलने की भी संभावना नहीं है। फोटो कॉपी को ही सबूत माना जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी दस्तावेज को सेकंडरी एविडेनस मानने के लिए यह साबित करना जरुरी है कि फोटोकॉपी मूल दस्तावेज से बनाई गई है, फोटोकॉपी का मिलान मूल दस्तावेज से किया गया हो, केवल मूल दस्तावेज के गुम होने का दावा पर्याप्त नहीं है। वरिष्ठ वकील के मुताबिक साक्ष्य अधिनियम में केस चलाने के लिए साक्ष्य पेश करने के लिए नियम तय हैं।

छावनी परिषद अधिकारियों पर Census Act के तहत कार्यवाही की संस्तुति

पथ प्रवाह, देहरादून

भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना प्रक्रिया के अग्रिम चरण में प्रवेश किए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी को प्रमुख जनगणना अधिकारी नामित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा अपेक्षा की गई है कि जनगणना चार्ज अधिकारियों की नियुक्ति, उनके साथ नियमित बैठकों का आयोजन, क्षेत्र निर्धारण, अंतर्विभागीय समन्वय, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण कर मंत्रालय को अवगत कराया जाए।

इसी क्रम में निदेशक जनगणना (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) एवं जिला प्रशासन देहरादून की संयुक्त बैठक 28 जनवरी 2026 को आहूत की गई। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैन्ट बोर्ड गढ़ी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद क्लेमनटाउन को विधिवत लिखित सूचना एवं दूरभाष के माध्यम से अवगत कराए जाने के बावजूद उनके द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया, जिस पर निदेशक जनगणना द्वारा कड़ा रोष व्यक्त किया गया।

इसके पश्चात 31 जनवरी 2026 को पुनः बैठक आयोजित की गई, जिसकी सूचना 28 जनवरी 2026 को ही प्रेषित कर दी गई थी। साथ ही अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा बैठक के महत्व को स्पष्ट करते हुए दोनों छावनी परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर संपर्क कर बैठक में प्रतिभाग करने का अनुरोध किया गया। इसके बावजूद दोनों अधिकारी पुनः बैठक में अनुपस्थित रहे।

अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण संबंधित छावनी क्षेत्रों का क्षेत्र निर्धारण नहीं हो सका तथा जनगणना से संबंधित प्रारम्भिक कार्यवाही भी आरंभ नहीं हो पाई। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए निदेशक जनगणना (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जिला प्रशासन देहरादून को संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध ष्टद्गठ्ठह्यह्वह्य ्रष्ह्ल, 1948 के अंतर्गत कार्यवाही की संस्तुति की गई है।

जिला प्रशासन देहरादून एवं निदेशक जनगणना द्वारा संयुक्त रूप से ष्टद्गठ्ठह्यह्वह्य ्रष्ह्ल, 1948 की धारा 6, 7 एवं 11 के अंतर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है, जिसमें एक माह तक के कारावास का प्रावधान भी शामिल है।

मणिपुर में तेजी से पलायन शुरू

मारवाड़ी पंजाबी जैन बंगाली कारोबारियों का पलायन?

मणिपुर। मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन का 1 साल पूरा हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन में मणिपुर की कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। मणिपुर में 3 साल से अशांति फैली हुई है। इंफाल वेली से म्यांमार बॉर्डर तक कहीं के भी हालत सामान्य नहीं है। अभी भी लोग शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए विवश हैं। कुकी और मैतई समुदाय के लोग एक दूसरे के इलाके में नहीं जा पा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी और अस्पतालों की सेवा भी लगभग ढप्प पड़ी हुई है।

मणिपुर में 16 जिले हैं। जिनमें से 8 जिलों में आज भी अशांति बनी हुई है आए दिन हमले होते हैं। 8 जिलों में हथियारबंद गिरोह जवरिया वसूली कर रहे हैं। पेट्रोल पंपों से रंगदारी मांगी जा रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होने के बाद भी मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। आए दिन पेट्रोल पंपों को बंद करा दिया जाता है। पेट्रोल डीजल ब्लैक में बिक रहा है। बोतल में बिक रहे पेट्रोल को नया नाम दे दिया गया है। बोतल ऑयल कॉरपोरेशन अर्थात बीओसी के नाम से पेट्रोल डीजल की बिक्री हो रही है।

मणिपुर में कुछ भी सामान्य नहीं है। यहां पर गैस सिलेंडर ?2000 मे ब्लैक में बिक रहा है। हर वक्त डर का माहौल बना रहता है। कुकी और मेतई समुदाय के युवा आपस में भिड़ते रहते हैं। यहां का युवा वर्ग अब मणिपुर छोड़कर अन्य राज्यों में पलायन कर रहा है। मणिपुर के युवा असम कोलकाता दिल्ली मुंबई में जाकर काम करने के लिए विवश हो रहे हैं।

मणिपुर के विभिन्न बाजारों में मारवाड़ी, पंजाबी, जैन, बिहारी और बंगाली समुदाय के लोग यहां पर व्यापार कर रहे थे। रंगदारी और असुरक्षा के कारण उन्हें बहुत घाटा हुआ है। बार-बार बाजार बंद हो जाता है। माल की आवाजाही में कठिनाई हो रही है। यहां के व्यापारी कर्ज में डूब चुके हैं। कर्ज और असुरक्षा के कारण वह भी मणिपुर से पलायन कर रहे हैं। जिसके कारण यहां के लोगों की समस्या और भी बढ़ती चली जा रही है।

मणिपुर में उग्रवादी संगठनों का एक तरह से कब्जा हो गया है। मेतई और कुकी उग्रवादी संगठन अपने-अपने क्षेत्र में लगातार वसूली कर रहे हैं। उग्रवादी कारोबारियों से 10,000 से लेकर ?100000 तक की वसूली के लिए दबाव बनाते हैं। आसानी से यहां पेट्रोल डीजल और रसोई गैस तक नहीं मिलती है। जिसके कारण यहां के लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। राष्ट्रपति शासन को लगे हुए एक साल होने को आ रहा है। उसके बाद भी स्थितियों में कोई सुधार नहीं है। ऐसा लगता है, केंद्र सरकार ने मणिपुर को भगवान भरोसे छोड़ दिया है।

रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी धमकी.......अबकी बार छाती पर चल सकती है गोली

मुंबई। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हाल ही में फायरिंग की घटना हुई, जिसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली और चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई, तो अगली बार बेडरूम में छाती पर गोली चल सकती है। पोस्ट में यह भी लिखा गया कि यह पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए चेतावनी है।

सोशल मीडिया पोस्ट में गैंग के सदस्यों शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और हरमन संधू ने कहा कि उन्होंने कई बार रोहित शेट्टी को चेतावनी दी थी कि उनके काम में दखल न दें, लेकिन बात नहीं मानी गई। पोस्ट में लिखा गया, इसको ये छोटा सा ट्रेलर दिया है। अगर आगे फिर हमारी बात नहीं समझी गई, तो अब घर के बाहर नहीं, बल्कि बेडरूम में गोली चलेगी। इसकी छाती पर और आगे पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है।

हमले के बाद रोहित शेट्टी ने अगले दो दिनों के लिए अपने सभी सार्वजनिक और निजी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और सहयोगियों से भी घर न आने का आग्रह किया है और फिलहाल केवल कॉल और मैसेज के जरिए ही संपर्क में हैं। मुंबई पुलिस के साथ मिलकर वह जांच में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं और अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

इस घटना से बॉलीवुड इंडस्ट्री में खलबली मची हुई है। पिछले कुछ सालों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई बड़े स्टार्स को निशाना बनाया है। सलमान खान के घर के बाहर हमला हो चुका है, जबकि यूट्यूबर एल्विश यादव और एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर भी फायरिंग की घटनाएं हुई थीं। इसके अलावा, कनाडा में कपिल शर्मा के शो 'कैप्स कैफे' के दौरान भी गैंग ने कई बार फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी।

एक नजर

10, 20 और 50 के नोट निकलेंगे एटीएम से

नईदिल्ली। इन दिनों बाजार में 10, 20 और ?50 के नोटों की भारी कमी है। नोटबंदी के बाद से छोटे मूल्य के नोट एटीएम से नहीं निकलते हैं। रिजर्व बैंक भी छोटे नोटों को कम प्रिंट कर रही है। छोटे नोटों की आपूर्ति के लिए नए एटीएम लगाए जाएंगे। इस कमी को पूरा करने के लिए हाइब्रिड एटीएम लगाने का प्रस्ताव किया गया है। परीक्षण के तौर पर मुंबई में इसे लगाया गया है। जो सफलतापूर्वक काम कर रहा है। अब इसे देश भर के रेलवे स्टेशन, बाजार,अस्पताल और सरकारी कार्यालयों में लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद रिजर्व बैंक छोटे नोट को ज्यादा छापेगी। अभी बाजार में 500 के 86 फ़ीसदी नोट चलन में है। 100 और 200 के लगभग 10।9 फ़ीसदी नोट चलन में है।छोटे नोट मात्र 3।1 फ़ीसदी प्रचलन में है। छोटे नोटों की हालत खराब है। छोटे नोटों और सिक्कों की कमी के कारण आए दिन विवाद की स्थिति बनती है। इसको देखते हुए भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों में हाइब्रिड एटीएम लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इस एटीएम के माध्यम से बड़े नोटों को छोटे नोटों और सिक्कों में बदल सकेंगे।

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की अनुमति के बाद मुंबई की बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शाखा में इसका सफल परीक्षण हो चुका है। अप्रैल के बाद हाइब्रिड एटीएम लगाने का काम तेज हो जाएगा। इस एटीएम को राष्ट्रीय स्तर पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में सभी जिलों में लगाए जाने का प्रस्ताव है।

चार दिवसीय आदिवासी महाकुंभ संपन्न, 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे

मुलुग। तेलंगाना के मुलुग जिले में एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी महाकुंभ संपन्न हो गया। कुंभ के दौरान करीब 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। जानकारी अनुसार मुलुग जिले के मेदाराम क्षेत्र में जम्पन्ना वागु नदी की तलहटी पर एशिया का सबसे बड़ा चार दिवसीय आदिवासी महाकुंभ का संपन्न शनिवार को हुआ। आदिवासी महाकुंभ की खास बात यह है कि यहां न कोई मंदिर है ओर न ही कोई मूर्ति ही स्थापित की गई है। यहां सिर्फ प्रकृति और जंगल की पूजा की जाती है। इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने अनेक राज्यों से लोग पहुंचे हुए थे। इसे प्रयागराज कुंभ के बाद देश का सबसे बड़ा दूसरा धार्मिक समागम बताया जाता है। इसके इतिहास के संबंध में बताया जाता है कि इसकी शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी और इसका आयोजन हर दूसरे साल किया जाता है। इस बार चार दिन चले आयोजन में करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और धर्म लाभ ग्रहण किया है।

एससी-एसटी एक्ट खत्म कराने आंदोलन का ऐलान, सस्पेंड पीसीएस अफसर अग्निहोत्री का बड़ा बयान

कानपुर। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद सुर्खियों में आए निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अब एक और बड़ा ऐलान कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल उन्होंने एससी/एसटी एक्ट को लेकर खुला विरोध जताते हुए इसे 'काला कानून' बताया और इसे खत्म कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। अपने गृह जनपद कानपुर पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि सरकार तय समय के भीतर इस कानून को समाप्त करने के लिए संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाती है, तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। अलंकार अग्निहोत्री ने दावा किया कि एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज होने वाली 95 प्रतिशत से अधिक शिकायतें फर्जी होती हैं और इस कानून के कारण सामान्य वर्ग, ओबीसी और कई अन्य समुदाय भय और मानसिक तनाव में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर इसलिए चुप हैं क्योंकि उन्हें जांच एजेंसियों का डर सताता है। उनके मुताबिक, सरकार को आंदोलन से पहले सात दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा। अपने निलंबन और इस्तीफे के बाद पहली बार इतने विस्तार से अपनी बात रख रहे अलंकार ने कहा, कि अब वह प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए बिना किसी दबाव के अपनी बात रख पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में जो हालात बन रहे हैं, वे किसी एक कानून तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। उनका दावा है कि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए केंद्र स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए गए हैं और पूरे सिस्टम पर दबाव बनाया जा रहा है।

अलंकार अग्निहोत्री ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और इनकम टैक्स विभाग को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल डर का माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसकी वजह से सांसद और विधायक खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। उनके अनुसार, जनप्रतिनिधियों को यह डर रहता है कि आवाज उठाने पर जांच एजेंसियां उनके पीछे लगा दी जाएंगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि सामान्य वर्ग और ओबीसी समाज, जिन्हें लंबे समय तक सत्ताधारी दल का समर्थन आधार माना जाता रहा है, अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अलंकार के मुताबिक, इन वर्गों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई है। उन्होंने 2027 के चुनावों को लेकर दावा किया, कि मौजूदा हालात में चुनाव हुए तो केंद्र की मौजूदा सरकार को दहाई में भी सीटें मिलना मुश्किल होगा।

अब आया नया प्लेटफॉर्म, इसमें इंसानों की एंट्री नहीं, सिर्फ एआई एजेंट्स करेंगे इस्तेमाल

नई दिल्ली। अब एक नया प्लेटफॉर्म आ गया है, जिसे इंसान यूज नहीं कर सकेंगे। इसको मोल्टबुक नाम दिया है और यह रेडडिट प्लेटफॉर्म की तरह है। इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) एजेंट्स ही इस्तेमाल कर सकेंगे। मोल्टबुक को इंसान देख सकते हैं, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। यहां एआई एजेंट्स अपनी-अपनी राय रख रहे हैं और दूसरे एजेंट्स के साथ चैट कर रहे हैं। इस स्थिति को देखकर कई एक्सपर्ट चिंतित है। इसको डेटा प्राइवेसी के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। कुछ ही दिन के अंदर मोल्टबुक पर 1.52 लाख से ज्यादा एआई एजेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। यह मशीनों द्वारा सोशलाइज होने का अब तक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है।

मोल्टबुक असल में ओपनक्लू इकोसिस्टम का पार्ट है। ओपनक्लू एक ओपन-सोर्स पर्सनल एआई असिस्टेंट है, जिसे पीटर स्टाइनबर्गर ने तैयार किया है। इसकी शुरुआत एक वीकेंड प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी और कुछ ही समय में यह वायरल हो गई है1 स्टाइनबर्गर ने अपने ब्लॉग में बताया है कि एक सप्ताह में 20 लाख विजिटर्स मिले और गिटहब पर 1 से ज्यादा स्टार्स हासिल हुए हैं। ओपनक्लू, आम यूजर्स को अपने कंप्यूटर पर एआई एजेंट्स चलाने की सर्विस देता है। ये असिस्टेंट वॉट्सऐप, टेलीग्राम, डिसकोर्ड और माइक्रोसाफ्ट टीम जैसे चैट ऐप्स से आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। इसकी मदद से कैलेंडर मैनेज और फ्लाइट डिटेल्स आदि चेक कर सकते हैं। इसका नाम पहले क्लूडबोट था फिर एंटिरोपिक के साथ एक कानूनी केस के बाद इसे मोल्टबुक कहा गया।

मणिपुर में सरकार गठन की अटकलें तेज, बीजेपी के 20 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंचे

हाईकमान से आज हो सकती है अहम बैठक

इंफाल। मणिपुर में एक बार फिर सरकार गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य के 20 से अधिक भाजपा विधायक रविवार को पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अधिराजमायुम शारदा देवी के साथ इंफाल से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। ये सभी विधायक भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ होने वाली अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त होने से पहले सरकार गठन की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है।

इंफाल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मणिपुर भाजपा अध्यक्ष अधिराजमायुम शारदा देवी ने कहा कि एनडीए के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में एक 'लोकप्रिय और स्थिर सरकार' का गठन होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व राज्य की मौजूदा परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह ने भी दिल्ली बैठक को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। उन्होंने कहा कि इस बार सिर्फ भाजपा ही नहीं, बल्कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों के विधायकों को बुलाया गया है, जिससे किसी ठोस नतीजे की उम्मीद की जा सकती है। बिरेन सिंह ने यह भी याद दिलाया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 12 फरवरी को

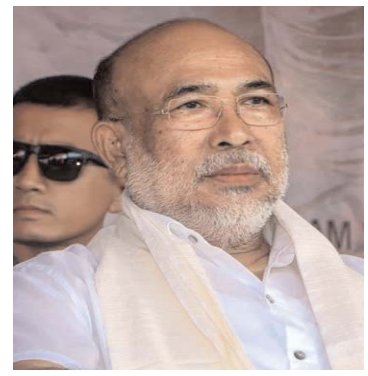

समाप्त हो रही है। इस दौरान लमसांग विधानसभा क्षेत्र के विधायक एस. राजेन सिंह ने कहा कि राज्य में सरकार बनने की संभावना है, हालांकि मुख्यमंत्री का फैसला पूरी तरह केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उन्होंने बताया कि बैठक संभवतः सोमवार शाम को होगी और राज्य की जमीनी स्थिति का आकलन करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं विधायक एच. डिंगो ने भी पुष्टि की कि बैठक सोमवार शाम को प्रस्तावित है, हालांकि एजेंडा अभी स्पष्ट नहीं किया गया है।

कुछ विधायकों को कोई जानकारी नहीं

कुछ विधायकों ने यह भी कहा कि उन्हें बैठक के उद्देश्य की पूरी जानकारी नहीं दी गई है। खुराई विधानसभा क्षेत्र के विधायक एल. सुसिंद्रो ने बताया कि उन्हें दिल्ली बैठक के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, हालांकि अन्य भाजपा और एनडीए विधायक भी शाम तक दिल्ली पहुंचने की संभावना है।

एनडीए की सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के प्रदेश अध्यक्ष लोरहो एस. फोजे ने कहा कि वह भी दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन सरकार गठन को लेकर फिलहाल कुछ भी निश्चित नहीं है। वहीं एनपीपी के नागा विधायक जे. पामेई ने भी बैठक में बुलाए जाने की पुष्टि करते हुए सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई। गौरतलब है कि मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा के चलते हालात बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। इस हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हुए हैं। फरवरी 2024 में एन. बिरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 37 विधायक हैं, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों के पास भी पर्याप्त संख्या है। ऐसे में दिल्ली में होने वाली यह बैठक मणिपुर की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम मानी जा रही है।

बेल्जियम से डिपोर्ट हुई केरल की नर्स को बड़ी राहत, पासपोर्ट जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला खारिज

नई दिल्ली। बेल्जियम से डिपोर्ट की गई केरल की एक नर्स को करीब एक दशक पुराने मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की गंभीर खामियों का हवाला देते हुए धोखाधड़ी और पासपोर्ट जालसाजी से जुड़े सभी आरोपों से नर्स को बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा कि आरोपी ने भारतीय इमिग्रेशन अधिकारियों को किसी तरह का धोखा दिया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रणव जोशी ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी लीना मारिया सूसाई के खिलाफ आगे मुकदमा चलाने के लिए कोई ठोस और विश्वसनीय आधार नहीं है। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों के साथ-साथ पासपोर्ट अधिनियम के तहत कथित रूप से जाली पासपोर्ट रखने के आरोप से भी बरी कर दिया। कोर्ट ने जांच में कस्टडी की उचित श्रृंखला की कमी, मूल दस्तावेजों की अनुपस्थिति और अभियोजन द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाए जाने जैसी गंभीर खामियों की ओर इशारा किया।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पूरा मामला बेल्जियम के इमिग्रेशन अधिकारियों के अपुष्ट आरोपों पर आधारित प्रतीत होता है। दिसंबर 2015 में लीना मारिया सूसाई नई दिल्ली से ब्रुसेल्स गई थीं, लेकिन अगले ही दिन बेल्जियम के अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट में कथित छेड़छाड़ का हवाला देते हुए उन्हें डिपोर्ट कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट मनोज तनेजा ने दलील दी कि उस समय सूसाई का मूल पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी और उन्हें भारत लौटने की अनुमति दे दी गई थी। मामले में एफआरआरओ (फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस) की शिकायत पर करीब आठ महीने बाद 2016 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उसी वर्ष सूसाई को अग्रिम जमानत मिल गई थी, जबकि चार्जशीट 12 जुलाई 2022 को दाखिल की गई। अदालत ने कहा कि नई दिल्ली से उनके प्रस्थान के समय भारतीय अधिकारियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था और मामला केवल डिपोर्टेशन के बाद शुरू किया गया।

कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि कथित अपराध विदेश में सामने आया था, ऐसे में अभियोजन पक्ष को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत यह साबित करना जरूरी था कि अपराध भारत में किया गया, लेकिन जांच इस अहम पहलू पर पूरी तरह मौन रही। इसके अलावा वियना कन्वेंशन के तहत प्रतिरक्षा के कारण बेल्जियम अधिकारियों से पूछताछ भी नहीं हो सकी। अदालत ने यह भी नोट किया कि पासपोर्ट भेजे जाने और उसके एफआरआरओ तक पहुंचने से जुड़े कोई पुख्ता रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए। एक पत्र में आरोपी का नाम हाथ से लिखा पाया गया, जबकि बाकी विवरण टाइप किए हुए थे और मूल दस्तावेज कभी अदालत के समक्ष पेश ही नहीं किए गए। इन सभी कारणों के आधार पर अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

बारामती विमान हादसे का मलबा और जले अवशेष की जांच की प्रक्रिया शुरु

विमान के पार्ट्स अलग-अलग स्थानों पर मिले, उन जगहों को किया मार्क

बारामती। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे से मलबा और जले हुए हिस्सों को इकट्ठा कर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विमानन प्राधिकरण और जांच एजेंसियों की टीम चार दिन बाद मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त ढांचे को हटाने का काम शुरू किया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी कर्मचारियों और मजदूरों की मदद से जले हुए हिस्सों को क्रेन के जरिए कंटेनर पर लोड किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि विमान के जो भी पार्ट्स अलग-अलग स्थानों पर मिले, उन जगहों को सफेद रंग से मार्क किया गया है, ताकि जांच के दौरान सटीक लोकेशन मैपिंग हो सके। बरामद जले हुए हिस्सों को लकड़ी के बक्सों में पैक कर फॉरेंसिक और तकनीकी परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। जांच एजेंसियां हादसे के कारणों का पता

लगाने के लिए सभी तकनीकी पहलुओं की पड़ताल करेंगी। दुर्घटना के बाद से घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट थी। बड़ी संख्या में लोग क्षतिग्रस्त विमान को देखने पहुंचे थे। अब हादसे वाली जगह से मलबा हटाने और साइट क्लियर करने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें यह हादसा 28 जनवरी 2026 की सुबह करीब 9:45 बजे लैंडिंग की कोशिश के दौरान हुआ था। एनसीपी नेता अजित पवार मुंबई से प्राइवेट विमान से चले थे। उन्हें बारामती में होने वाले कुछ कार्यक्रमों में शामिल होना था। बारामती पहुंचने पर विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com